out authorisation from an officer not below the rank of an Assistant Commissioner;

(b) if so, by when the above proposal would be brought in force;

(c) the details of export houses in Delhi on which raids by labour and factory inspectors were conducted during the last six months (monthwise); and

(d) the details of the discrepancies found and further action contemplated in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) The Delhi Administration had been considering steps to stremline and closely monitor the field work and inspections.It decided that all inspectors of the Labour Department (such as those of factory, boiler, electricity and labour) would require authorisation from atleast the Assistant Labour Commissioner (or equivalent rank officer in the factory, boiler and electricity inspectorates) of the zone in which they are posted in order to carry out inspections. This has nothing to do with any proposal of the Delhi Exporters' Association.

(b) The decision has been brought into force with effect from the 10th August, 1990.

(c) and (d) No raids on export houses were conducted during the last six months by the labour and factory inspectorates.

Amendment in Scheduled Caste/Scheduled Tribe Order (Amendment Act, 1976)

3624. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have received recently representations to bring an amendment to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders (Amendment) Act, 1976, to restore area restriction in case of Mochi Community of Gujarat which obtained prior to 1977;

(b) whether it is a fact that Government of Gujarat in October 1977 represented to area restriction to Mochi Community of only Dang District and Umarguan Taluka of Bulsar District and Government of India introduced an amendment Bill No. 84/78 on 12th May, 1978 to this effect and

(c) if so, what action Government propose to take for considering recommendation of Scheduled Castes Commissioner in his Report of 1986-87 to restore area specific scheduling to Mochi Community in Gujarat ?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) : Yes, Sir.

(c) All proposals, representations, suggestions, recommendations, etc. are under consideration of the Government and any amendment in the existing lists could be made only through an Act of Parliament as laid down in Articles 341(2) and 342 (2) of the Constitution.

देश में विधवा और निस्सहाय महिलाएं

3625. **श्री कपिल वर्मा :**

श्रीमती वीणा वर्मा :

डा. रूद्र प्रताप सिंह :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में विधवाओं तथा परित्यक्त महिलाओं को नारकीय जीवन बिताना पड़ता है; यदि हां, तो ऐसी महिलाओं की संख्या क्या है;

(ख) सरकार विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने तथा समाज में उनका स्तर ऊंचा उठाने की दिशा में क्या कदम उठाने का विचार रखती है तथा उनके कल्याण के लिए वर्तमान योजनाएं क्या हैं; और

(ग) 20–25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन के बाद पति द्वारा पत्नी को घर से निकाल दिए जाने पर तथा उस पत्नी द्वारा तलाक प्राप्त कर लेने पर पति की सम्पत्ति का आधा भाग उसे प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) सरकार को विधवाओं तथा परित्यक्त महिलाओं की समस्याओं की जानकारी है। किन्तु, ऐसी महिलाओं की संख्या का पता लगाने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा महिलाओं के लिए 27 महत्वपूर्ण लाभ प्रधान योजनाए कार्यान्वित की जा रही हैं । ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(ग) पत्नी को पति की सम्पत्ति और आय में बराबर की हिस्सेदार बनाने के सुझाव सरकार को कुछ क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे हैं । किन्तु इससे पहले कि सरकार इस मामले पर विचार करे, इस पर गहराई से अध्ययन करने और व्यापक सहमति की आवश्यकता है ।

विवरण

केवल महिलाओं के लिये 27 लाभ प्रधान योजनाओं का प्रबोधन

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम	लक्ष्य 1989–90 (लाख रु० में)	31–3–90 तक व्यय (लाख रु० में)
1	2	3	4
1.	**ग्रामीण विकास विभाग**		
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास	1149.00	901.41
2.	**शिक्षा विभाग**		
2.	केवल लड़कियों के लिये अनौपचारिक शिक्षा	1765.00	1202.86
3.	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**		
3.	एन० एन० एम०/आई० और एल० एच० वी० का प्रशिक्षण . . .	*1050.00	*1250.34
4.	दाइयों का प्रशिक्षण . .	*200.00	*129.43
5.	पोषाहारीय रक्तक्षीणता की रोकथाम के लिये रोग प्रतिरोधन . .	875.00	900.00
4.	**कल्याण मंत्रालय**		
6.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये गर्ल्स होस्टल . .	550.00	551.53
5.	**श्रम मंत्रालय**		
7.	महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (योजना और गैर योजना) . .	65.76	44.45

1	2	3	4
	8. महिलाओं के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विविधीकरण विस्तार	15.00	12.94
	9. हिसार (हरियाणा) में आर० वी० टी० आई० की स्थापना . .	5.00	3.24
	10. एन० वी० टी० आई० और आर० वी० टी० आई० में प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षणों का आयोजन और प्लेसमेंट सैल की स्थापना करना। . .	1.00	—
	11. अतिरिक्त आर० वी० टी० आई० की स्थापना।	10.00	10.65
	12. नई दिल्ली, बम्बई और बंगलौर में महिलाओं के लिये आर० वी० टी० आई०/एन० वी० टी० आई० को सुदृढ़ बनाना . .	32.00	9.05
	13. डी० जी० ई० एण्ड टी० के नई दिल्ली मुख्यालय में महिला सैलों को सुदृढ़ बनाना/ महिलाओं के प्रशिक्षण के लिये निदेशालय की स्थापना करना . . .	1.00	—
	14. महिला आई० टी० आई० स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	175.00	102.00
	15. विकलांग महिलाओं का पुनर्वास (महिलाओं के लिये दो वी०आर०सी० की स्थापना)	7.60	5.99
6.	**महिला एवं बाल विकास विभाग**		
	16. कामकाजी महिला होस्टल . .	500.00	556.00
	17. महिलाओं के लिये रोजगार और आय वर्धक= सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (नोराड)	200.00	201.28
	18. प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम . . .	282.50	282.48
	19. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम . .	300.00	299.97
	20. ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिये जागृति विकास परियोजना . .	47.50	41.15
	21. महिला विकास निगम . .	200.00	166.20
	22. संकटग्रस्त महिलाओं का पुनर्वास	20.00	20.00
	23. महिलाओं/लड़कियों के लिये अल्पावाह गृह	95.00	95.00
	24. कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिये शिशु गृह/दिवस देखभाल केन्द्र .	1537.00	1537.00

2	3	4
25. समेकित बाल विकास सेवा . .	18100.00	18044.00
7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
26. महिलाओं के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग . . .	55.00	69.91
8. कृषि और सहकारिता विभाग		
27. बैकवार्ड पोल्टरी डिवेल्पमेंट (घरों में मुर्गी खाना खोलना) . .	12.00	9.63

Electric Connection in servant quarters in Lodhi Colony

3626. SHRI RAMSINH RATHWA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether separate electric connections have not been provided in servant quarters attached to type-IV flats in Block Numbers 20, 21 and 23 in Lodhi Colony;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to give separate electric connections in servant quarters attached to the flats in Block Numbers 20, 21 and 23 in Lodhi Colony; and

(d) if so, by when ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) As the type IV quarters in Block numbers 20, 21 & 23 in Lodhi Colony were constructed in the pre-Independence period, it is not known, at this stages, as to why separate electric connections were not provided in the servant quarters attached to these quarters. As, according to the existing policy, type IV quarters are not entitled to separate servant quarters, there is no proposal to provide electric connections in these quarters.

(d) Does not arise in view of reply to (a), (b) & (c) above.

Legislation for Ban on cow slaughter

3627. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have issued any directions to various State Governments to enact legislation for imposition of ban on cow slaughter;

(b) the names of the States which have enacted legislations imposing the ban with the dates of enactment. State-wise; and

(c) the names of the States which have not done so and the reasons therefor in each case ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR) : (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Fixation of Price of free sale sugar by Sugar Factories

3628. SHRIMATI SURYAKANTA PATIL : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of Maharashtra Rajya Sahkari Sakhar Karkhana Sangh Ltd. has recently announced to sell the free sale sugar not less than Rs. 725/- a quintal exclusive of taxes;

(b) whether it is also a fact that this price (Rs. 725/- a quintal) is less than the break-even price of Rs. 820/- a quintal;

(c) if so, what is Government's reaction in this regard; and

(d) what steps Government propose to take to fix the price of free sale sugar with sugar factories and what is being done to compensate the sugar factories for